डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 16 मई, 2025, डिस्पेच दिनांक 16 मई, 2025

| वर्ष 68 | अंक 24 | भोपाल | 16 मई, 2025 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सहकारिता की शक्ति से वैश्विक व्यापार की ओर भारत : अमित शाह

- **केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की प्रगति की समीक्षा की**
- **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में बनी ये राष्ट्रीय सहकारी संस्थाएं "Whole of Government" एप्रोच के साथ छत्र संगठन के रूप में कार्य कर रही हैं**
- **NCEL को सहकारी चीनी मिलों से चीनी, त्रिपुरा के सुगंधित चावल, जैविक कपास, और मोटे अनाज के निर्यात के नए अवसर तलाशने का सहकारिता मंत्री का निर्देश**
- **श्री अमित शाह ने खाड़ी देशों में ताज़ी सब्जियों के निर्यात और विशेष आलू किस्मों के लिए बड़ी कंपनियों के साथ भागीदारी का सुझाव दिया**
- **केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने NCEL को रु.2 लाख करोड़ के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया और कहा कि ऐसे तीन विशिष्ट उत्पादों की पहचान की जाए जिन्हें भारत से वर्तमान में निर्यात नहीं किया जा रहा है**
- **केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि NCOL वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु.300 करोड़ से अधिक के कारोबार का लक्ष्य रखके कार्य करे**
- **भारत के बीज पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में BBSSL की महत्वपूर्ण भूमिका महत्वपूर्ण – श्री अमित शाह**
- **गृह मंत्री ने उच्च चीनी मात्रा और कम जल आवश्यकता वाली गन्ना किस्म पर भी कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया**
- **गुजरात के कलोल में स्थापित अत्याधुनिक बीज अनुसंधान केन्द्र अरहर, उड़द, मक्का जैसी फसलों की उच्च उपज, कम परिपक्वता और कम जल आवश्यकता वाली किस्मों का विकास करेगा**
- **केला उत्पादक शीर्ष 10 राज्यों के लिए उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टिशू कल्चर सुविधा की स्थापना करना अति-आवश्यक**

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में सहकारिता मंत्रालय के सचिव, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, तथा श्री अनुपम कौशिक, श्री विपुल मित्तल और श्री चेतन जोशी (क्रमशः NCEL, NCOL और BBSSL के प्रबंध निदेशक) उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से सहकारिता मंत्रालय द्वारा इन तीनों राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं को बनाया गया था, जिनका उद्देश्य सहकारी निर्यात, जैविक उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण बीजों के प्रचार के लिए छत्र संगठन के रूप में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि इनका संचालन संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के सहयोग से 'Whole of the Government' दृष्टिकोण के तहत किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में अनेक पहलें एवं ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत हुई हैं जिससे सहकारी क्षेत्र को तेज गति से बढ़ावा मिल रहा है।

NCEL (नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड)

श्री अमित शाह ने कहा कि NCEL को सहकारी चीनी मिलों से चीनी, त्रिपुरा के सुगंधित चावल, जैविक कपास, और मोटे अनाज के निर्यात के नए अवसर तलाशने का निर्देश दिया । श्री अमित शाह ने खाड़ी देशों में ताज़ी सब्जियों के निर्यात और विशेष आलू किस्मों के लिए बड़ी कंपनियों के साथ भागीदारी की संभावनाओं का भी सुझाव दिया।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने NCEL को रु.2 लाख करोड़ के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया और कहा कि ऐसे तीन विशिष्ट उत्पादों की पहचान की जाए जिन्हें भारत से वर्तमान में निर्यात नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही, सभी सहकारी संस्थाओं के निर्यात को NCEL के माध्यम से करने का निर्देश दिया ताकि लगभग रु.20,000-30,000 करोड़ का कारोबार और करों व संचालन लागत के बाद शुद्ध लाभ वापस सहकारी समितियों को मिल सके।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दलहन आयात हेतु अफ्रीका और म्यांमार में NCEL के कार्यालय स्थापित करने तथा एक समर्पित वेबसाइट विकसित करने का भी सुझाव दिया, जिससे सहकारी सदस्य वैश्विक मांग को समझ सकें और अपनी आपूर्ति क्षमता साझा कर सकें।

NCEL को मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था और अपने पहले वर्ष में इसने उल्लेखनीय प्रगति की है। FY 2024-25 में इसने 10,000 से अधिक सहकारी संस्थाओं को सदस्यता दी और रु.4,283 करोड़ का कारोबार किया, जिसमें रु.122 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ।

NCEL ने 28 देशों में अपने निर्यात को बढ़ाया है, जिनमें मुख्य उत्पाद हैं: बासमती और गैर-बासमती चावल, समुद्री उत्पाद (विशेषकर झींगा), मोटे अनाज, गेहूं, फल-सब्जियाँ, पशु उत्पाद, मसाले और बागान उत्पाद। इसने सेनेगल, इंडोनेशिया तथा नेपाल के 61 आयातकों के साथ रणनीतिक समझौते (MoUs) भी किए हैं।

NCOL (नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड)

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने NCOL के संबंध में कहा कि NCOL द्वारा प्राप्त जैविक उत्पाद Amul, Bigbasket जैसे बड़े ब्रांडों को भी आपूर्ति किए जा रहे हैं जिससे 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के लिए अधिक मात्रा और लागत लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री अमित शाह ने कहा कि जल्द ही इसके उत्पाद रिलायंस स्टोर्स में पूरे भारत में उपलब्ध होंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मार्गदर्शन में 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के तहत 22 उत्पाद वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध हैं और इसे प्रमुख महानगरों में लॉन्च करने की योजना है। उत्पादों में अनाज, दालें, मसाले और मिठास उत्पाद शामिल हैं। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने NCOL के प्रयासों की सराहना करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु.300 करोड़ से अधिक के कारोबार का लक्ष्य रखा। उन्होंने राज्य स्तर पर प्रमाणित जैविक किसानों के समूह बनाने और उन्हें उच्च स्तर पर एकीकृत करने का भी निर्देश दिया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाणिज्यिक संचालन के शून्य वर्ष में ही NCOL ने विभिन्न वर्गों में 7000 से अधिक सहकारी संस्थाओं को सदस्यता दी और 1200 मीट्रिक टन से अधिक की मात्रा का लेनदेन किया, जो 2000 से अधिक किसानों से प्राप्त किया गया। इसका कारोबार अब तक रु.10.26 करोड़ रहा है। ब्रांड की विशिष्टता इसकी 'प्रामाणिकता और वहनीयता' के दृष्टिकोण के मद्देनजर हर उत्पाद बैच का कीटनाशक अवशेषों की जांच 'जैविक भारत' मानकों के अनुसार की जा रही है और उसकी रिपोर्ट उपभोक्ताओं के साथ QR कोड के रूप में साझा किया जा रहा है और यह ग्राहक उन्मुख पहल इस उद्योग में पहली बार लागू किया गया है।

BBSSL (भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड)

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत के बीज पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में BBSSL की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि केला उत्पादक शीर्ष 10 राज्यों के लिए उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टिशू कल्चर सुविधा की स्थापना करना अति-आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुजरात के कलोल में हाल ही में स्थापित किया गया अत्याधुनिक बीज अनुसंधान केन्द्र अरहर, उड़द, मक्का जैसी फसलों की उच्च उपज, कम परिपक्वता और कम जल आवश्यकता वाली किस्मों के विकास हेतु कार्य करेगा। उन्होंने उच्च चीनी मात्रा और कम जल आवश्यकता वाली गन्ना किस्म पर भी कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री अमित शाह ने BBSSL को NDDB और अमूल के नेटवर्क के माध्यम से बिक्री हेतु लचका चारा फसल के बीच विकसित करने का आग्रह किया है। श्री अमित शाह ने प्रोसेसिंग किस्मों के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू जैसी प्रोसेसिंग किस्मों हेतु बीज उत्पादन को प्रोत्साहन दिये जाने पर भी बल दिया। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने ब्रीडर सीड्स की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से समन्वय कर आवश्यक ब्रीडर बीजों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने BBSSL के प्रयासों की सराहना की और सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया—कि वह नवाचार, गुणवत्ता इनपुट्स और संस्थागत समर्थन के माध्यम से कृषि सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाएगी।

कृषि आधारित उद्योगों के लिए सरल और अनुकूल हैं राज्य सरकार की नीतियां : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

3812 करोड़ की लागत की 11 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन

6 हजार 850 लोगों को मिलेगा रोजगार

निवेशकों के लिये सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं

ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

संभाग और जिला स्तर पर भी होंगे कृषि उद्योग समागम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खाद्य प्र-संस्करण उद्यमियों से किया संवाद

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदसौर जिले के सीतामऊ में आयोजित 'कृषि उद्योग समागम-2025' में 'खाद्य प्र-संस्करण उद्यमियों से संवाद' कार्यक्रम में कहा कि खुशहाल कृषक और उन्नत कृषि मध्यप्रदेश की पहचान है। खाद्य प्र-संस्करण से जहां उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं किसान भी आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संचालित राज्य सरकार का संकल्प भी यही है। कृषि आधारित उद्योगों के लिए हमारी सरकार सरल व अनुकूल नीतियों का निर्माण कर उद्यमियों को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज 3812 करोड़ की लागत की 11 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण, भूमि-पूजन हुआ है। इससे स्थानीय स्तर पर 6850 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कृषि संबंधी उद्योगों की संभावनाओं पर निवेशकों से चर्चा की। साथ ही नीमच-मंदसौर जिले में नवीन उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को आशय प्रमाण पत्र (लेटर ऑफ इन्ट रेस्टो) भी प्रदान किए गये हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार के दरवाजे निवेशकों के लिए हमेशा खुले हैं। सरकार निवेशकों के मार्ग की सभी बाधाएं हटाने का काम कर रही है। हम सब प्रदेश की उन्नति के लिए संकल्पबद्ध हैं। सरकार हरसंभव सहयोग के लिए निवेशकों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बिजली पानी एवं बेहतर सड़क की सुविधा के साथ ही औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीतियां उपलब्ध हैं। औद्योगिक निवेश के लिए प्रदेश में बेहतर वातावरण है। उन्होंने कहा कि प्रति बीघा गेहूं के उत्पादन में मध्यप्रदेश ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले इस तरह के आयोजन बड़े शहरों में ही होते थे, परंतु अब हमने संभाग एवं जिला स्तर पर भी इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने का निर्णय लिया है और इसकी शुरुआत आज मंदसौर जिले से हुई है। राज्य सरकार सभी प्रकार के निवेशकों को समान रूप से निवेश के अवसर उपलब्ध करा रही है।

मुख्य सचिव श्री अनुरागजैन ने कहा कि मध्यप्रदेश को रोजगारोन्मुखी बनाना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिकता है। उनका मानना है कि इसके लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की ग्रोथ रेट देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। जीडीपी में भी कृषि का योगदान 44 प्रतिशत है। प्रदेश में सिंचाई के रकबे में हुई वृद्धि से कृषि क्षेत्र में उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। मंदसौर, नीमच क्षेत्र मसालों के लिए विख्यात रहा है। यहां खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों में पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार में सरलता के लिए राज्य सरकार ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री अनुपम राजन ने कहा कि कृषि उद्योग समागम की पहली कड़ी सीतामऊ मंदसौर में आयोजित हुई है। इसमें विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशा के अनुरूप इस प्रकार के समागम संभाग और जिला स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण की पर्याप्त संभावना विद्यमान है। इस संबंध में राज्य शासन की नीतियां भी निवेशकों, उद्योगपतियों के लिए अनुकूल हैं और राज्य सरकार भी खाद्य प्र-संस्करण को प्रदेश में नई ऊंचाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री चंद्रमौली शुक्ला ने निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत विभिन्न नीतियों के संबंध में जानकारी दी। उद्योगपति श्री अजय भटनागर ने भी अपने अनुभव साझा किए। निवेशकों से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, मंदसौर जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री श्री निर्मला भूरिया, जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में उद्योगपति एवं निवेशक उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश में कृषि और उद्योग का समन्वय आत्मनिर्भरता की दिशा में दूरगामी पहल : प्रभारी मंत्री श्री काश्यप

भोपाल :एमएसएमई और भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री श्री चैतन्य काश्यप ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कृषि और उद्योग के समन्वय का अनूठा प्रयोग प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में नई क्रांति ला रहा है। कोर्टयार्ड बाय मैरियट में आयोजित "मध्यप्रदेश में गन्ना फसल एवं शुगर कारखानों के सतत् विकास" सम्मेलन में मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि खेती भारत की आत्मा है और एमएसएमई विभाग के माध्यम से शुगर फैक्ट्रियों की स्थापना से किसानों को बेहतर मार्केटिंग, तकनीकी सहायता एवं वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे ग्रामीण आर्थिक विकास को नई गति मिल रही है।

सम्मेलन में प्रदेश के एमएसएमई और कृषि विभाग के अधिकारी, उद्योगपति तथा किसान प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 3 मई को मंदसौर में आयोजित बड़े कृषि समारोह में कृषि मेले में उद्योगों को शामिल करने का यह पहला प्रयास मध्यप्रदेश की नई दृष्टि को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि सिंचित क्षेत्र 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 55 से 60 लाख हैक्टेयर तक पहुंच गया है, जिससे प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

प्रभारी मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने और उत्पादकता के साथ जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। शुगर मिलों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये भूमि, बिजली और ऋण योजनाओं में विशेष रियायतें दी जा रही हैं। इससे कृषि क्षेत्र को बल मिलेगा, बेरोजगारी में कमी आएगी और आर्थिक समृद्धि के नए आयाम खुलेंगे।

प्रभारी मंत्री श्री काश्यप ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि कृषि और उद्योग का यह सम्मिलन आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में एक सकारात्मक और दूरदर्शी पहल है, जो किसानों और उद्योग दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

पशुपालन से ही खेती लाभ का व्यवसाय बनेगा : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

गौमाता की सेवा से मानव जाति का होगा कल्याण

प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ के सम्मेलन का किया शुभारंभ

प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 50 लाख लीटर प्रतिदिन होगा - पशुपालन राज्य मंत्री श्री लखन पटेल

भोपाल : उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा जिले के होटल विजय विलास में आयोजित प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ के सम्मेलन का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि निराश्रित और बीमार गौवंश की सेवा तथा पुनर्वास वर्तमान समय की बड़ी चुनौती है। सरकार आधुनिक गौशालाओं का निर्माण कराकर निराश्रित गौवंश को आश्रय देने तथा खेती को बचाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में उन्नत गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें हजारों गायों को नया जीवन मिलेगा। इस अभियान में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। गौमाता की सेवा से ही मानव जाति का कल्याण होगा। अगर गौमाता बेसहारा रही तो मानव जाति का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा में बसामन मामा गौवन्य विहार में सात हजार से अधिक निराश्रित गायों को आश्रय दिया गया है। इन गायों की सेवा में पशु चिकित्सक बड़ी तत्परता और लगन से कार्य कर रहे हैं। शीघ्र ही हिनौती में भी आधुनिक गौशाला शुरू होगी जिसमें लगभग 25 हजार गौवंश को रखने का लक्ष्य रखा गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पशुपालन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाना आवश्यक है। पशुपालन को अपनाकर ही किसान खेती को लाभ का व्यवसाय बना सकेंगे। गौवंश को दूध न देने पर बेसहारा छोड़ने की मानसिकता है। गौमाता यदि दूध नहीं दे रही है तो भी उसका गोबर और गौमूत्र बहुमूल्य है। गौमाता में देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए गोबर का उपयोग पूजा में भी किया जाता है। आधुनिक गौशालाओं में गोबर से अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाने के साथ सीएनजी प्लांट लगाए जा रहे हैं। पशु चिकित्सकों की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर तो रोगी से पूछकर उसका इलाज करते हैं। पशु चिकित्सक बेजुबान पशुओं के लिए भगवान की तरह हैं।

बाबा साहब अंबेडकर गौ संवर्धन योजना से डेयरी को मिलेगा नया आयाम - मंत्री श्री पटेल

पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री श्री लखन पटेल ने कहा कि पशुपालन विभाग को विभिन्न नवाचारों के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सदैव पशुपालन विभाग को प्राथमिकता दी है। डेयरी के विकास के लिए बाबा साहब अंबेडकर गौ संवर्धन योजना लागू की गई है। इसमें कम से कम 25 दुधारू पशु की एक यूनिट बनाई गई है। प्रत्येक यूनिट पर पशुपालक को अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से डेयरी व्यवसाय को नया आयाम मिलेगा। अभी प्रदेश में 10 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन संग्रहण होता है। इसे 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। समारोह में पशु चिकित्सा अधिकारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मेडिकल के डॉक्टरों की तरह पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। पशु चिकित्सा संघ की सभी उचित मांगे पूरी की जाएंगी। पशु चिकित्सा अधिकारियों का कार्य मानव के डॉक्टरों से अधिक कठिन और महत्वपूर्ण है। प्रदेश में हेल्पलाइन 1962 की गाड़ियों से पशुओं का उपचार बेहतर हुआ है। इन गाड़ियों की संख्या दुगनी करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में निराश्रित गौवंश बड़ी चुनौती हैं। बेसहारा गायों के लिए प्रदेश में 22 स्थानों पर शीघ्र ही आधुनिक गौशालाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। सरकार दो वर्षों में सभी बेसहारा गायों को गौशाला में व्यवस्थित कर देगी तब सड़कों पर गौवंश नहीं दिखेगा। गौशालाओं को पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल की तरह विकसित करेंगे।

पशु चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ मनोज गौतम ने कहा कि सरकार ने गौशाला के गौवंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन से राशि बढ़ाकर 40 रुपए कर दी है। इसी तरह आधुनिक डेयरी निर्माण के लिए भी ऋण और अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारी शामिल रहे। समारोह में अतिथियों और सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा अधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला का संचालन श्री अवनीश शर्मा ने किया।

ग्रीष्मकालीन मूंग में खरपतवार नाशकों के उपयोग को करें हतोत्साहित

भोपाल : हरित क्रांति से हमारे देश ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता हासिल कर ली है। मध्यप्रदेश देश की खाद्य सुरक्षा को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अनाज के साथ-साथ दलहन के शीर्ष तीन उत्पादक राज्यों में मध्यप्रदेश एक है। यहाँ के किसान न केवल अनाज, तिलहन और दलहन का उन्नत उत्पादन करते हैं। माइको इरिगेशन, सुनिश्चित आवश्यक बिजली प्रदाय और सुलभ ऋण तक बेहतर पहुंच के कारण उच्च मूल्य वाली उद्यानिकी फसलों की खेती से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम समय के साथ नवीन समस्याओं का भी उदय देख रहे हैं, जिनका समाधान किया जाना भी आवश्यक है।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के ग्वालियर वाईस चांसलर रहे प्रो. (डॉ.) विजय सिंह तोमर का कहना है कि किसान वर्तमान में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती बड़े स्तर पर कर रहे हैं। जो 10 साल पहले तक, बड़े पैमाने पर खरीफ में की जाती थी और यह पर्यावरण के लिए अनुकूल थी। इसकी खेती वर्षा आधारित परिस्थितियों में की जाती थी। मूंग के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मौजूदगी होने से यह फसल मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है। आज मूंग की खेती का क्षेत्रफल तीन गुना से भी अधिक बढ़ गया है, लेकिन यह फसल गर्मियों में उगाई जाने लगी है, इसलिए इससे भू-जल स्तर का अत्यधिक दोहन लगातार हो रहा है। किसान मूंग की बोनी जल्द करने के लिए फसलों के अवशेषों को जलाने पर जोर देते हैं, जिसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में मूंग की अतिरिक्त सिंचाई से बिजली की खपत में भी वृद्धि होती है। राज्य सरकार ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। किसानों को नरवाई के सही उपयोग के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा।

किसानों द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग को जल्दी सुखाने के लिए खरपतवार नाशक पैराक्वेट एवं ग्लाइफोसेट का उपयोग किया जा रहा है, इससे फसल जल्दी पक जाती है। इसका दुष्प्रभाव वातावरण के साथ ही उत्पादित मूंग का सेवन करने वाले आमजन पर भी होता है। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बढ़ने की संभावना होती है।

लगातार खरपतवार नाशकों का उपयोग मिट्टी में उपयोगी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता घटती है. साथ ही ग्रीष्मकालीन मूंग में कम से कम 3-4 बार सिंचाई करना पड़ती है। इससे भूमि का जल स्तर निरंतर नीचे जा रहा है।

किसानों को खेती के लिए अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा रहा है। किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन मूंग जो प्राकृतिक रूप से पकता है, उसमें कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक का उपयोग न के बराबर किया जाये।

डॉ. तोमर ने कहा कि आज यदि डॉ. स्वामीनाथन जीवित होते तो वे इस बात से सहमत होते कि हरित क्रांति ने देश को बहुत कुछ दिया। आज खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य पौध संरक्षण रसायनों के उपयोग की होड़ लगी हुई है। इससे मृदा जीव को नुकसान और जल निकाय स्रोत ने प्रदूषण की संभावना बढ़ गई है। इसी प्रकार पौध संरक्षण रसायनों के अनियंत्रित उपयोग के परिणामस्वरूप हमारे द्वारा ग्रहण किये जाने वाले भोजन में रासायनिक अवशेषों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप बीमारियों और नवीन स्वास्थ्य विकारों के मामलों में वृद्धि हुई है।

मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आगे : कृषि मंत्री

भोपाल : किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। साथ ही फसलों के उत्पादन में रिकार्ड बनाया। प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, खाद्यान उत्पादन में द्वितीय स्थान पर एवं तिलहन उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। तृतीय फसली क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। नरवाई जलाने को हतोत्साहित करने कुछ प्रतिबंध भी लगाये गये है। इसमें नरवाई जलाने की घटना वाले कृषकों को आगामी एक वर्ष के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार रूपये का भुगतान नहीं किये जाने साथ ही आगामी एक वर्ष के लिए उनकी उपज का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं करना भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषि उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अंतर्गत कई कार्यक्रम किये जा रहे है, जिससे प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। खरीफ 2024 के धान उत्पादक कृषकों को जिन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया है, उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। चार हजार रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जायेगा, जिसमें एक कृषक को अधिकतम दस हजार रूपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदाय की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा रबी 2024-25 में उपार्जित गेहूँ पर 175 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 83.50 लाख से अधिक किसानों को लगभग 1770 करोड़ रुपए उनके खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 24 फरवरी, 2025 को जमा किए गए है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 10 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 81 लाख से अधिक किसानों को 1624 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते में सिंगल क्लिक से जमा किए गए हैं।

प्रदेश में पहली बार भारत सरकार की सपोर्ट प्राइस स्कीम में सोयाबीन का उपार्जन किया गया, जिसमें 2 लाख 12 हजार 568 कृषकों से 6.22 लाख मीट्रिक मात्रा का उपार्जन किया गया, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि 3043.04 करोड़ रुपए है। श्रीअन्न के उत्पादन को बढावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न (मोटा अनाज) प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसमें किसानों को 3900 रुपए प्रति हैक्टेयर डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खाते में देय होंगे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ ही फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि का लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल के नुकसान का समय पर आंकलन एवं राहत राशि का वितरण किसानों को समय पर मध्यप्रदेश में मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन और दावा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एनसीआईपी पोर्टल के साथ अपने भूमि रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक एकीकृत करने एवं इस पोर्टल को और अधिक किसान अनुकूल बनाने के लिए 'उत्कृष्टता प्रमाण पत्र' प्रदान किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु शासन द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजनांतर्गत प्रदेश में 89 दीदियों को स्वावलंबी बनाया गया है। इनके माध्यम से 4200 हैक्टेयर में तरल उर्वरक का छिड़काव तथा राशि रूपये 21.22 लाख की शुद्ध आय प्राप्त की। इस वर्ष 2025-26 में 1066 दीदियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। कृषकों को फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिये शासन द्वारा कई कदम उठाये गये हैं, जिसमें प्रदेश स्तर पर 46,800 से अधिक नरवाई प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्र अनुदान पर वितरित करते हुए 412 करोड़ रूपये की अनुदान राशि जारी की गई है।

प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस एवं गेल कंपनी द्वारा स्थापित किये जा रहे सीबीजी प्लांट में फसल अवशेष से कम्प्रेस बायो गैस निर्माण की जायेगी, इसके लिये राज्य सरकार ने नरवाई प्रबंधन से संबंधित हाईटेक हब केन्द्र स्थापना पर हितग्राही को अधिकतम 97.50 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदाय किये जाने के लिये विभागीय कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से ट्रैक्टर सर्विस मैकेनिक तथा कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण देश की प्रतिष्ठित निर्माता कंपनी के सहयोग से दिया जाता है। विभागीय केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 2024-25 तक 7361 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें से 1939 प्रशिक्षणार्थियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ। कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से किसान ड्रोन पायलट प्रशिक्षण एवं ड्रोन तकनीशियन का प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। प्रशिक्षण में 50 प्रतिशत शुल्क का भुगतान राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। कुल 412 युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण तथा 33 प्रशिक्षणार्थियों को ड्रोन तकनीशियन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कृषकों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाये जाने के लिये शासन के जन संकल्प पत्र-2023 के अनुपालन में हर वर्ष 1000 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। पूरे देश में इस योजना की पहल मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2012 में की गई तथा अब तक 4730 कस्टम हायरिंग केन्द्र प्रदेश स्तर पर स्थापित होकर कृषकों को लाभ दे रहे है। आवेदक को प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 25 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 10 लाख का अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में APEDA अन्तर्गत 11.48 लाख हैक्टयर फसल उत्पादन क्षेत्र एवं वनोपज संग्रहण क्षेत्र सहित 20.55 लाख हेक्टेयर जैविक क्षेत्र पंजीकृत है। "एक जिला-एक उत्पाद" अंतर्गत कृषि संबंधी 06 उत्पाद कोदो-कुटकी-अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, तुअर दाल-नरसिंहपुर, चना-दमोह, बासमती चावल-रायसेन, चिन्नोर चावल-बालाघाट, सरसों-भिण्ड एवं मुरैना, अंतर्गत 10 जिले शामिल किये गये है।

फार्म गेट ऐप के तहत किसान अपनी उपज का विवरण, फोटो मोबाइल एप्लिकेशन पर डाल कर मंडी मे पंजीकृत व्यापारियों के साथ मोल भाव कर सकता है। सौदा तय होने पर किसान की सहमति प्राप्त कर व्यापारी सीधे किसान के गाँव या खेत से उपज उठा लेता है। इससे भौतिक रूप से माल के परिवहन की आवश्यकता नहीं रहती। यह उपज न बिकने की अनिश्चितता को समाप्त करता है। मंडी में सही दाम न मिलने पर भी, विशेषकर छोटे और मध्यम किसान जिनके पास अपने परिवहन के साधन नहीं होते है, उन्हें अब मजबूरी में उपज नहीं बेचना पड़ती है। भाड़े की बचत होती है। मंडी के माध्यम से किसान को मंडी अनुबंधित व्यापारी का चयन कर खेत या गोदाम पर ही फसल को बेचने की सुविधा है।

मुख्यमंत्री ने की गेहूं उपार्जन की समीक्षा

कोई भी किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित नहीं रहे, सभी किसानों का किया जाए गेंहू उपार्जित : मुख्यमंत्री

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गेंहू उपर्जान के लिए कोई भी किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित नहीं रहे और बुकिंग वाले सभी किसानों का गेंहू उपार्जित किया जाए। किसानों को कोई परेशानी न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उपार्जन केंद्रों पर किसी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक 8 लाख 87 लाख से हजार से अधिक पंजीकृत किसानों से 76.60 लाख मैट्रिक टन गेंहू उपार्जित हुआ है। किसानों को 5 मई तक 16 हजार 472 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम पिछले वर्ष का रिकार्ड तोड़ते हुए इस वर्ष 81 लाख मैट्रिक टन गेंहू उपार्जन लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। यह प्रदेश के किसानों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को अन्नदाताओं पर गर्व है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रबी उपार्जन अंतर्गत गेहूं उपार्जन की समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) डॉ. राजेश राजौरा उपस्थित थे।

बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2025-26 में 34 लाख 93 हजार एकड़ रकबे में हुए गेंहू उपार्जन के लिए 15 लाख 44 हजार किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया। प्रदेश में 3 हजार 620 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए। स्लॉट बुकिंग से शेष किसानों की बुकिंग के लिए पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन किसानों से गेंहू का उपार्जन 9 मई तक किया जाएगा।

किसान के खेत से निकलता है विकसित भारत का रास्ता : उप राष्ट्रपति

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों के साथ हुआ परस्पर संवाद कार्यक्रम

राज्यपाल श्री पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया भी कार्यक्रम में हुए शामिल

भोपाल : उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से निकलता है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं और कृषि विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के जीवन में बदलाव एवं खुशहाली लाने में अपना योगदान दें। प्रयास ऐसे हों कि किसान केवल फसल उत्पादक बनकर ही न रहें, अपितु वे एग्री-प्रीनियर (कृषि उद्यमी) बनें। उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ रविवार को ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों के परस्पर संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कृषि विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे तकनीक और अनुसंधान का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में बदलाव के प्रबंधक बनें।

संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उप राष्ट्रपति की धर्मपत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ और विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला मंचासीन थे। इस अवसर पर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि भारतीय संस्कृति किसानों के कल्याण का संदेश देती है। वर्तमान दौर में किसानों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री ने "जय जवान–जय किसान" का नारा दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने "जय जवान–जय किसान के साथ जय विज्ञान" जोड़ा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "जय जवान–जय किसान–जय विज्ञान में जय अनुसंधान" को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि कृषि विद्यार्थी विज्ञान और अनुसंधान के केन्द्र बिंदु होते हैं। इसलिए विद्यार्थी इस कसौटी पर खरे उतरकर किसानों के कल्याण के लिए काम करें। उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि किसानों को अपनी उपज तत्काल न बेचनी पड़े, इसके लिये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दें और वेयर हाउस एवं कोल्ड स्टोर स्थापित कर किसानों को भण्डारण के लिए प्रेरित करें। श्री धनखड़ ने कहा कि किसान अपनी परेशानी व्यक्त करें, उससे पहले ही हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि किसान क्या चाहते हैं।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और उनके लिये सकारात्मक नीतियां बनाई हैं। सरकार ने सहकारिता को भी कृषि में अध्याय के रूप में जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सीधे धनराशि पहुँच रही है।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया एवं समाजसेवी दत्तोपंत ठेंगड़ी के सुकृत्यों को याद करते हुए कहा कि सुखद संयोग है कि ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय का नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया एवं सभागार का नाम दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नाम पर है। इसलिये यह विश्वविद्यालय दो ऐसी महान आत्माओं का संगम है जो राष्ट्रवाद और समाज के कल्याण के लिये समर्पित रहीं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी यह संकल्प लें कि इन विभूतियों के आदर्शों पर चलकर हम सदैव राष्ट्र हित को सर्वोपर्य रखेंगे।

मध्यप्रदेश में गौ-संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों को सराहा

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा गौवंश के संरक्षण के उद्देश्य से गौशालाओं को दिए जा रहे प्रोत्साहन की प्रशंसा की। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री डॉ. यादव से राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की गौशाला के विस्तार में सहयोग के लिये कहा।

कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान की परिपाटियों को विश्व स्तरीय बनाएँ : राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि मानव सभ्यता के उद्भव और विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी के लिये कृषि आज भी आजीविका की जीवन रेखा बनी हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी दूरदृष्टि दृष्टिकोण के साथ किसानों को समृद्ध व सशक्त बनाकर विकसित भारत बनाने के लिये लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विकास और परिवर्तन के केन्द्र बिंदु विश्वविद्यालयों को अध्ययन व अनुसंधान की मौजूदा परिपाटियों को विश्व स्तरीय बनाना होगा। साथ ही तेजी से बदलती जलवायु को ध्यान में रखकर नई तकनीकों के द्वारा खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना होगा। राज्यपाल श्री पटेल ने विश्वविद्यालयों से सामूहिक रूप से कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया।

कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे कार्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदलेंगे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कृषि और पशुपालन के कार्य प्रदेश की अर्थ व्यवस्था बदलने का कार्य करेंगे। लगभग दो वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश का कृषि क्षेत्र 45 लाख हेक्टेयर था जो आज की स्थिति में 55 लाख हो गया है। प्रदेश में एक करोड़ हेक्टेयर कृषि क्षेत्र निर्मित करने का राज्य सरकार का संकल्प है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है, इस नाते निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रदेश में नर्मदा और अन्य नदियों के जल से सिंचाई का कार्य हो ही रहा है। विश्व की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना केन-बेतवा मंजूरी के बाद पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्षों से यह परियोजनाएं लंबित थीं। आने वाले समय में प्रदेश में बुंदेलखण्ड, चंबल और मालवा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का उल्लेखनीय विकास होगा। इन परियोजनाओं से मध्यप्रदेश का नक्शा बदलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अनेक राष्ट्रों में कम क्षेत्र में अधिक अनाज उत्पादन का कार्य हो रहा है। मध्यप्रदेश में जहां उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को कृषि संकाय के महत्व से अवगत करवाकर आवश्यक अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्थाएं की जा रही हैं वहीं लाभकारी फसलों के उत्पादन को महत्व दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि के सहयोगी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। जो भी व्यक्ति गोपालन करता है वह गोपाल है और हमारा घर-घर गोकुल है। राज्य सरकार ने 25 से अधिक गाय पालने पर 25 प्रतिशत की अनुदान राशि प्रदान करने और गोपालकों से दूध खरीदने का संकल्प लिया है। गौशालाओं को भूमि प्रदान करने की पहल भी की गई है। इसी तरह बड़े नगरों में 10-10 हजार गायों के पालन के लिए 30 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। अब अपाहिज और बेसहारा गायों के लिए जुर्माने के प्रावधान को खत्म कर सरकार द्वारा गायों की देखरेख का व्यय वहन किया जा रहा है। प्रदेश में देश के 9 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन को 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि विश्वविद्यालय में आगमन के लिए उप राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। साथ ही राजमाता विजयाराजे सिंधिया एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी का श्रद्धाभाव के साथ स्मरण कर उनके द्वारा समाज व देश हित में किए गए कार्यों को रेखांकित किया।

देश में कृषि के क्षेत्र में हो रहे हैं क्रांतिकारी काम: केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया

केन्द्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम हो रहे हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मध्यप्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। कैन बेतवा एवं काली सिंध – पार्वती व चंबल नदी जोड़ों परियोजना इसी का प्रतिफल है। उन्होंने यह भी कहा कि देश अमृतकाल से शताब्दी काल की ओर अग्रसर है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक देश आत्मनिर्भर ही नहीं, विश्व गुरू के रूप में स्थापित हो। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों से कहा कि आप सब कल का भारत हो, इसलिये देश के विकास की दिशा में नई क्रांति लाने के वाहक बनें। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया के सदकार्यों पर भी प्रकाश डाला।

स्वागत उदबोधन विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला ने दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय में कृषि के क्षेत्र में किए गए नवाचार, विश्वविद्यालय से जुड़े कृषि विज्ञान केन्द्र व महाविद्यालयों के बारे में जानकारी दी।

आरंभ में उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ सहित सभी अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आगाज एवं समापन राष्ट्रगान जन-गण-मन के गायन के साथ हुआ।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने किया "प्राकृतिक खेती इकाई एवं मॉडल गौशाला" का लोकार्पण

उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में "प्राकृतिक खेती इकाई एवं मॉडल गौशाला" का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। लोकार्पण के बाद सभी अतिथियों ने यहाँ लगाई गई गौ उत्पादों पर केन्द्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और गौ-माताओं को चारा खिलाया।

उप राष्ट्रपति डॉ. धनखड़ सहित सभी अतिथियों ने "प्राकृतिक खेती इकाई एवं मॉडल गौशाला" के उदघाटन के बाद एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी रोपे। पौधरोपण के बाद उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि वृक्षारोपण को और तेज करें। हम सब न केवल पेड़ लगाएं बल्कि उनका संरक्षण भी करें।

सहकारिता मंत्रालय और स्विगी इंस्टामार्ट के बीच समझौता : सहकारी उत्पाद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

केन्द्रीय सहकारिता सचिव की उपस्थिति में, सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) में शामिल करने के लिए सहकारिता मंत्रालय और स्विगी (Swiggy) के बीच समझौता

सहकारी समितियां भी तकनीक उपयोग से नए ग्राहकों से जुड़ सकेंगी

अब 'भारत ऑर्गेनिक्स' और अन्य सहकारी डेयरी उत्पाद Swiggy के ई-कॉमर्स और क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे

Swiggy विपणन, प्रचार, उपभोक्ता प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहकारी ब्रांडों का समर्थन करने के लिए मंत्रालय के साथ काम करेगी

Swiggy के प्लेटफॉर्म पर समर्पित "सहकारी" श्रेणी बनाई जाएगी, जिसमें ऑर्गेनिक्स, डेयरी, बाजरा और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय 60 से अधिक पहलों के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र को नई ऊँचाइयों पर पहुंचा रहा है

नई दिल्ली, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी की उपस्थिति में सहकारिता मंत्रालय और स्विगी इंस्टामार्ट के बीच सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। स्विगी इंस्टामार्ट के सीईओ (CEO) श्री अमितेश झा और सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री डी के वर्मा के बीच समझौता ज्ञापन पर शुक्रवार 25 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से सहकारी समितियों को नए जमाने की तकनीकों के माध्यम से नए जमाने के ग्राहकों से जुड़ने में सुविधा होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने देश के सहकारी क्षेत्र को संवर्धित करने के लिए 60 से अधिक पहल की हैं। हाल ही में मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र से जैविक उत्पादों सहित सहकारी उपज को बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं। समझौता ज्ञापन के बाद, भारत ऑर्गेनिक्स और अन्य सहकारी डेयरी उत्पाद अब स्विगी के ई-कॉमर्स और क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य Swiggy के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आउटरीच का लाभ उठाकर भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है। यह साझेदारी Swiggy के इंस्टामार्ट प्लेटफॉर्म पर सहकारी डेयरी उत्पादों को शामिल करने को प्रोत्साहित करेगी और सहकारी संस्थाओं के लिए अधिक दृश्यता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समर्थन प्रदान करेगी। Swiggy विपणन, प्रचार, उपभोक्ता प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहकारी ब्रांडों का समर्थन करने के लिए मंत्रालय के साथ काम करेगी। Swiggy के प्लेटफॉर्म पर एक अलग "सहकारी" श्रेणी बनाई जाएगी, जिसमें ऑर्गेनिक्स, डेयरी, श्री अन्न , हस्तशिल्प और सहकारी संगठनों द्वारा विकसित और प्रचारित अन्य उत्पादों पर ध्यान दिया जाएगा। यह सहयोग सहकारी समितियों को नए जमाने की प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नए जमाने के उपभोक्ताओं से जुड़ने में सुविधा प्रदान करेगा, जिससे उनके डिजिटल पदचिह्न का विस्तार होगा और उनकी बाजार उपस्थिति बढ़ेगी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने के मद्देनजर, Swiggy, सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर, देशभर में सहकारी आंदोलनों, संगठनों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा।

24 अप्रैल 2025 को सचिव सहकारिता डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया था, जो दालों और जैविक खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पैकेजिंग के लिए समर्पित है, जो स्वच्छता और गुणवत्ता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करता है।

देशभर के 700 से अधिक जिलों में 29 मई से चलेगा 'विकसित कृषि संकल्प अभियान': केंद्रीय कृषि मंत्री

किसानों से गांवों में जाकर संवाद करेंगे कृषि वैज्ञानिक- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह

विकसित भारत के लिए हमारा संकल्प है विकसित खेती और समृद्ध किसान- श्री शिवराज सिंह

विकसित खेती व किसानों के फायदे के लिए रचनात्मक, महत्वाकांक्षी, अभिनव अभियान- श्री शिवराज सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड के मंत्र को साकार करके किसानों के लिए बड़ी कवायद

विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ली बैठक

दिल्ली, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा देशभर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह अभियान 700 से ज्यादा जिलों में 29 मई से प्रारंभ होकर 12 जून तक चलेगा। इस दौरान हमारे कृषि वैज्ञानिक एवं मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय कृषिकर्मियों के साथ टीम बनाकर प्रतिदिन अलग-अलग गांवों में पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद करेंगे तथा उन्हें खेती-किसानी के संबंध में अपने स्तर पर और जागरूक करेंगे, विभिन्न सलाह देंगे। यह सारी कवायद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए "लैब टू लैंड" के मंत्र को साकार करने के लिए की जा रही है। आधुनिक व आदर्श खेती के साथ ही, यह "एक देश, एक कृषि, एक टीम" की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक भी दिल्ली में आयोजित की, जिसमें देशभर के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के साथ ही देशभर में फैले आईसीएआर के 100 से अधिक संस्थानों तथा कृषि विज्ञान से जुड़े अन्य संस्थानों के साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हाईब्रिड मोड में शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी तथा आईसीएआर के महानिदेशक डा. एम.एल. जाट भी उपस्थित थे।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि इस रचनात्मक व महत्वाकांक्षी अभियान के पीछे मकसद यहीं है कि हमारी खेती उन्नत-विकसित हो और हमारे किसानों को इसका सीधा फायदा मिलें। पूरे अभियान के दौरान उन्नत तकनीकों, नई किस्मों व सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाएगा, साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना भी उद्देश्य है। अभियान में चार-चार वैज्ञानिकों की टीमें, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सुझाई गई विभिन्न

(शेष अगले पृष्ठ पर)

चावल और मक्का में उल्लेखनीय वृद्धि सहित देश के खाद्यान्न क्षेत्र में 3.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी- श्री शिवराज सिंह चौहान

खरीफ 2024 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.81 प्रतिशत की वृद्धि, जिसमें चावल, मक्का और ज्वार आदि फसलों में उच्च उत्पादन- श्री शिवराज सिंह

उत्पादन वृद्धि में योगदान के लिए सभी को बधाई और हमारे किसानों की मेहनत को प्रणाम- केंद्रीय मंत्री

खरीफ में आवश्यकता से ज्यादा 178.48 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध, सीड रिप्लेसमेंट की दर बढ़ना खुशी की बात- शिवराज सिंह

रासायनिक उर्वरकों के कुप्रभावों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने बनाया प्राकृतिक कृषि मिशन- श्री शिवराज सिंह

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन- खरीफ 2025 अभियान में की पत्रकारों से चर्चा

नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के पूसा कैंपस स्थित अग्नि हॉल में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन- खरीफ 2025 अभियान में हुई चर्चा के साथ-साथ खरीफ की बुआई से पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तैयारियों व रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर सहित विभिन्न राज्यों से आए कृषि मंत्री भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आज राज्यों के कृषि मंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकार तथा आईसीएआर एवं अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों व वर्चुअल जुड़े सभी पदाधिकारियों के साथ सारगर्भित चर्चा हुई है। राज्यों के बेहतर प्रदर्शन, किसानों की मेहनत और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण खरीफ के रकबे में वृद्धि हुई है, वहीं खरीफ 2023-24 के दौरान चावल का क्षेत्रफल 40.73 मिलियन हेक्टेयर था, जो खरीफ 2024-25 में 43.42 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। चावल का उत्पादन खरीफ 2023-24 में 113.26 मिलियन टन था, जो खरीफ 2024-25 में 120.68 मिलियन टन हो गया है। इसी तरह, खरीफ में 2023-24 के दौरान मक्का का क्षेत्रफल 8.33 मिलियन हेक्टेयर था, जो खरीफ 2024-25 में 8.44 मिलियन हेक्टेयर हो गया और मक्के का उत्पादन खरीफ 2023-24 में 22.25 मिलियन टन था, जो खरीफ 2024-25 में 24.81 मिलियन टन हो गया है।

श्री शिवराज सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में कुल खाद्यान्न क्षेत्र में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें चावल और मक्का में प्रमुख वृद्धि देखी गयी है। समान रूप से खरीफ 2024 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष 2023 खरीफ उत्पादन की तुलना में 6.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें चावल, मक्का और ज्वार आदि फसलों में उच्च उत्पादन देखा गया है। उन्होंने कहा कि विपरीत जलवायु परिस्थितियों के बावजूद हमारे खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। रबी का भी द्वितीय अनुमान बेहद आशाजनक है। आईसीएआर के हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कई नई जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास के कारण यह लक्ष्य अर्जित हुआ है। राज्यों ने भी बेहतर ढंग से खेती में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है। उत्पादन वृद्धि में योगदान के लिए श्री शिवराज सिंह ने सभी को बधाई दी और कहा कि हमारे किसानों की मेहनत को प्रणाम करता हूं।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि आगे आने वाले खरीफ के मौसम में हम नई किस्मों के बीज ठीक ढंग से किसानों के पास पहुंचा पाएं, इसके लिए प्रयासरत है। व्यापक स्तर पर अच्छे बीज किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काफी चर्चा हुई है। श्री चौहान ने कहा कि लैब टू लैंड की नीति के तहत वैज्ञानिक और किसान साथ मिलकर काम करे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। प्रसन्नता की बात है कि हमारे पास आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय को मिलाकर 16 हजार वैज्ञानिक हैं, जिनके योगदान को शामिल करते हुए, किसानों तक शोध की सही जानकारी पहुंचाने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनाई गई है। इस बार खरीफ की फसल के लिए, जो आमतौर पर 15 जून के बाद शुरू होती है, उसी के मद्देनजर 4-4 वैज्ञानिकों की टीम बनाई जाएगी, इनके साथ राज्यों के कृषि विभाग का अमला जुड़ेगा, केंद्र सरकार के कृषि विभाग के साथी भी जुड़ेंगे, प्रगतिशील किसान जुड़ेंगे और यह 15 दिन खरीफ फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए अच्छे बीज, बेहतरीन तकनीक का लाभ दिलाने के लिए संवाद होगा। एक दिन में तीन स्थानों पर एक टीम जाएगी और किसानों से सार्थक संवाद करेगी, जिसमें अच्छे बीज के बारे में, कृषि पद्धितियों के बारे में, जलवायु अनुकूल बुआई के बारे में, उचित फसल के निर्णय के लिए विस्तार से चर्चा करके ये टीम किसानों को दिशा देने का काम करेगी।

श्री चौहान ने कहा कि जहां तक खरीफ में बीज का सवाल है, बीज की आवश्यकता है 164.254 लाख क्विंटल की और हमारे पास पर्याप्त बीज 178.48 लाख क्विंटल उपलब्ध है। हम सभी राज्यों की मांग के अनुसार उन्नत बीज उपलब्ध करा पाएंगे। खुशी की बात ये है कि सीड रिप्लेसमेंट की दर बढ़ रही है। पहले किसान परंपरागत बीज बोते रहते थे लेकिन 10 साल से पहले सीड बदल देना चाहिए। 10 साल हो जाने पर बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती। बीज बदलने की प्रवृत्ति में तेजी आ रही है, जिसके लिए मैं लिए राज्यों को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता के लिए काम किया जा रहा है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के किसानों के लिये यूरिया, डीएपी, एनपीके की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। विदेश में बढ़ रही कीमत के बावजूद सब्सिडी किसानों को मिल रही है। हमने खाद को स्टोर करना शुरू कर दिया है।

श्री चौहान ने कहा कि गेहूँ, चावल हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता है लेकिन दलहन और तिलहन का हमें आयात करना पड़ता है। भारत सरकार ने जो दलहन मिशन शुरू किया है उसे इम्प्लीमेंट करने की बात सम्मेलन में हुई है। उत्पादन कैसे बढ़े, इस पर भी चर्चा और ऑइल सीड के उत्पादन को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। एक और प्रमुख विषय है अत्यधिक उर्वरकों का इस्तेमाल। रासायनिक उर्वरकों के कुप्रभावों से बचने के लिए प्राकृतिक कृषि मिशन भारत सरकार ने बनाया है। कंविन्स करके किसान के जमीन के टुकड़े पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। 33 राज्यों का एनुयल एक्शन प्लान आ गया है। 7.78 लाख हेक्टेयर में 15,560 क्लस्टर बनाए जाएंगे और 10 हजार बायो रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। 16 प्राकृतिक खेती के केंद्रों की पहचान की गई है और 3,100 वैज्ञानिकों को किसान को मास्टर ट्रेनिंग के रूप में ट्रेन किया गया है। कम से कम 18 लाख किसान प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें, 1 करोड़ किसानों को हम सेन्सीटाइज़ करें, इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि ये बैठक बहुत गंभीरता से हुई है। हमने तय किया है कि रबी की बैठक एक नहीं, दो दिन की होगी। हमने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि जो भेदभावपूर्ण सिंधु जल समझौता किया गया था, जिसमें 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान के हिस्से में और केवल 20 प्रतिशत हिस्सा भारत के हिस्से में है, उसे रद्द किया गया है। इसका लाभ किसानों को मिलेगा। विशेषकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अधिक पानी के कारण उत्पादकता बढ़ेगी, बाढ़ नियंत्रण जैसे काम भी बेहतर होंगे। किसानों को बिजली भी मिलेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

फसलों में संतुलित खादों के प्रयोग के लिए जागरूक व शिक्षित करेगी। केवीके, आईसीएआर के संस्थानों व इफको आदि द्वारा कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रदर्शन भी किया जाएगा एवं किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आई.सी.टी. का व्यापक उपयोग होगा। धान की सीधी बुवाई (डी.एस.आर), फसल विविधीकरण, सोयाबीन की फसल में मशीनीकरण जैसी उन्नत तकनीकों का प्रसार भी केवीके के विशेषज्ञ करेंगे। टीमों में राज्य कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन विभागों, आत्मा के अधिकारी, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस) से जुड़े पौध संरक्षण अधिकारियों के साथ प्रगतिशील किसान, कृषि उद्यमी, एफपीओ/ एफआईजी/स्वयं सहायता समूहों के सदस्य भी शामिल होंगे।

बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के लिए हमारा संकल्प है विकसित खेती और समृद्ध किसान और किसानों को अगर समृद्ध बनाना है तो तरीका है कि वे ठीक ढंग से खेती करें। हम जो विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर रहे हैं, ये कर्मकांड नहीं है। ये ऐसा कार्यक्रम भी नहीं है कि हम आज शुरू कर रहे हैं और 10-20 साल बाद इसका नतीजा आएगा, बल्कि ये एक ऐसा अभिनव कार्यक्रम है कि हम आज शुरू करेंगे व तीन महीने बाद खरीफ सीजन में ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखने की पूरी उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरा मानना है कि कृषि में जो रिसर्च हो रहे हैं, वो किसानों के पास खेतों तक पहुंचना चाहिए। अभियान के जरिये किसानों में जिज्ञासा व रूचि पैदा होगी व वैज्ञानिक भी उत्साहित होंगे। श्री चौहान ने वैज्ञानिकों से कहा कि ये कार्य वे मन से करेंगे तो इसका देश को, किसानों को बहुत फायदा होगा।

इस संबंध में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे हैं, साथ ही केंद्रीय कृषि सचिव श्री चतुर्वेदी व आईसीएआर के महानिदेशक डा. जाट ने भी अपने-अपने स्तर पर राज्यों के उच्चाधिकारियों से संवाद किया है। अभियान की सफलता के लिए इसकी विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है

एफपीओ सशक्तिकरण हेतु मध्यप्रदेश में राज्य सहकारी संघ एवं एनसीडीसी का संयुक्त क्षेत्रीय भ्रमण: सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी

भोपाल : मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों—देवास, उज्जैन, धार, खरगोन, और रायसेन—में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सहकारी संघ, भोपाल और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के अधिकारियों द्वारा संयुक्त क्षेत्रीय भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में सहकारिता विभाग के अधिकारी और संबंधित जिलों के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।

भ्रमण का उद्देश्य

- एफपीओ की प्रगति और प्रबंधन क्षमता का प्रत्यक्ष निरीक्षण।
- MIS पोर्टल पर अद्यतन जानकारी और रिपोर्टिंग व्यवस्था की समीक्षा।
- MIS पोर्टल पर नियमित डेटा प्रविष्टि और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।
- एफपीओ के लिए उपयुक्त व्यावसायिक गतिविधियों का चयन।
- स्थानीय संसाधनों पर आधारित व्यावसायिक गतिविधियों जैसे प्रसंस्करण, विपणन, और मूल्यवर्धन को प्राथमिकता देना।
- निर्वाचित संचालक मंडल की भूमिका और स्थानीय सहभागिता की मजबूती।
- एफपीओ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) एवं लेखापाल की शीघ्र नियुक्ति।
- सदस्यता वृद्धि के लिए ग्रामस्तरीय जागरूकता अभियान और किसानों से सीधा संवाद स्थापित करना।

देवास जिला

देवास जिले में सोनकच्छ, देवली, और बरोठा एफपीओ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एफपीओ की प्रगति, प्रबंधन क्षमता, और MIS प्रणाली की स्थिति की समीक्षा की गई। भ्रमण दल में राज्य सहकारी संघ से डॉ. योगेश नामदेव, श्री संतोष येडे, श्री रोबिन सक्सेना, और एनसीडीसी से श्री गौरव जाधौन शामिल थे। सहकारिता विभाग के उपयुक्त सहकारिता और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक देवास के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

उज्जैन जिला

उज्जैन जिले में नलवा, कायथा, लखेसरा, और घूमर एफपीओ का निरीक्षण किया गया। समीक्षा बैठक में उपायुक्त सहकारिता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक उज्जैन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एफपीओ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, और संचालक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। राज्य सहकारी संघ के विशेषज्ञों ने एफपीओ प्रबंधन को MIS पोर्टल की दक्षता, डेटा प्रविष्टि, तथा व्यवसाय रणनीतियों पर दिशा-निर्देश दिए। एनसीडीसी के प्रतिनिधि श्री गौरव जाधौन ने एफपीओ की स्थिरता हेतु CEO एवं लेखापाल की शीघ्र नियुक्ति, बैंक खातों के सक्रिय संचालन और नियामक पालन पर बल दिया।

धार जिला

धार जिले में तोरनोद, सिंघाना, और तिरला एफपीओ का निरीक्षण किया गया। बैठक में एफपीओ की वर्तमान कार्यप्रणाली, व्यावसायिक गतिविधियाँ, प्रबंधन संरचना तथा आगामी रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। राज्य सहकारी संघ से श्री संतोष येडे, डॉ. योगेश नामदेव, और श्री रोबिन सक्सेना विशेष रूप से उपस्थित रहे। सहकारिता विभाग, धार से श्री योगेंद्र शर्मा, लेखा अधिकारी, और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक धार की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी की प्रतिनिधि श्रीमती ममता जी ने भी बैठक में सहभागिता की।

खरगोन जिला

खरगोन जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें खरगोन, खेतियाँ और मर्दाना क्षेत्र के एफपीओ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडल सदस्य, और पैक्स प्रबंधकों ने भाग लिया। बैठक में उपायुक्त सहकारिता श्री काशीराम अवासे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री पी. एस. धनवाल, और राज्य सहकारी संघ भोपाल से श्री संतोष येडे, डॉ. योगेश नामदेव, और श्री रोबिन सक्सेना विशेष रूप से उपस्थित रहे।

रायसेन जिला

रायसेन जिले में माँ नर्मदा कृषक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डूमर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सहकारी संघ के विशेषज्ञ श्री संतोष येडे, डॉ. योगेश नामदेव, और अन्य विशेषज्ञों ने एफपीओ की संरचना, उद्देश्य, संचालन, और व्यावसायिक रणनीतियों पर विस्तृत जानकारी साझा की। शाखा प्रबंधक, पैक्स प्रबंधक, और एफपीओ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं संचालक मंडल के सदस्य भी उपस्थित रहे।

इन संयुक्त क्षेत्रीय भ्रमणों और बैठकों के माध्यम से एफपीओ की कार्यप्रणाली में सुधार, पारदर्शिता, और व्यावसायिक दृष्टिकोण को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी ने इस प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाया। यह पहल प्रदेश के एफपीओ को आर्थिक सशक्तता और सामूहिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला एक प्रेरणास्पद कदम है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।